



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 13, Issue 4, April 2024

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

स्वयं सहायता समूह (SHG) के क्रियान्वयन में नाबार्ड की भूमिका एवं बाड़मेर में विकास की पहल

अनिता महला

शोधार्थी (भूगोल विभाग),
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

स्वयं सहायता समूह (SHG) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस शोध पत्र में नाबार्ड की SHG क्रियान्वयन में भूमिका, विकास की पहल, और इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा। परिणामस्वरूप बाड़मेर में सफलता की कहानी में SHG की भूमिका का विवेचन करेंगे।

मूल शब्द : सामाजिक-आर्थिक विकास, व्यवसायिक और प्रबंधकीय क्षमता, संस्थागत विकास

पृष्ठभूमि :

नाबार्ड की भूमिका : नाबार्ड ने SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP) को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य SHGs को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना है। नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित मुख्य गतिविधियों की जाती हैं:

- वित्तीय सहायता :** नाबार्ड SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके तहत, SHGs को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे वे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। नाबार्ड स्वयं सहायता समूहों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता बैंकों के माध्यम से होती है, जिससे समूहों को आर्थिक संबल मिलता है। सहायता राशि का वितरण, नाबार्ड विभिन्न योजनाओं के तहत SHGs को सहायता राशि वितरित करता है, जिससे उन्हें आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने में मदद मिलती है।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण :** नाबार्ड SHGs के सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसका उद्देश्य समूह के सदस्यों की व्यवसायिक और प्रबंधकीय क्षमताओं को विकसित करना है। SHGs के सदस्यों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, आदि।

3. **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम** : SHGs के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे अपने वित्तीय संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन कर सकें।
4. **संस्थागत विकास** : नाबार्ड SHGs के विकास के लिए संस्थागत विकास पर जोर देता है। इसके तहत, स्थानीय संस्थाओं और NGO के साथ मिलकर SHGs को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। नाबार्ड विभिन्न NGO और स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर SHGs के लिए सहयोग प्रदान करता है। संस्थागत नेटवर्क: नाबार्ड एक मजबूत संस्थागत नेटवर्क तैयार करता है, जिससे SHGs को आवश्यक संसाधन और सहायता प्राप्त होती है।
5. **नवाचार और प्रौद्योगिकी** : नाबार्ड ने SHGs के विकास के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया है। डिजिटल वित्तीय समावेशन में डिजिटल माध्यमों के उपयोग से SHGs को वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इससे समूहों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ आसानी से मिल पाता है। तकनीकी सहयोग के अंतर्गत नाबार्ड SHGs को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है, जिससे वे अपने व्यवसायों में नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर सकें।
6. **विकासात्मक पहल** : नाबार्ड SHGs के समग्र विकास के लिए कई विकासात्मक पहल करता है। इनमें शामिल हैं:

ग्रीन इनिशिएटिव्स : पर्यावरणीय स्थायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड हरित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मार्केट लिंकेज SHGs के उत्पादों को बाजार में पहुँचाने के लिए नाबार्ड सहायता प्रदान करता है, जिससे समूहों की आय में वृद्धि हो सके।

आंकड़े और विश्लेषण : नाबार्ड की SHG पहल के परिणामस्वरूप विभिन्न आर्थिक और सामाजिक लाभ हुए हैं। इन लाभों को निम्नलिखित सारणियों और आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है—

वर्ष 2020–2023 में नाबार्ड द्वारा SHGs को प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है—

- 2020 में कुल स्वयं सहायता समूहों की संख्या पच्चीस हजार से बढ़कर 2024 बत्तीस हजार हो गयी, वही वित्तीय सहायता पन्द्रह हजार करोड़ से बाइस हाजर करोड़ रुपये है। जिसमे प्रति SHG औसत सहायता 60000 से 70000 तक है।
- SHG के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक – 2020 एवं स्वरोजगार से जुड़ी महिलाएं 10.5 लाख से बढ़कर 2024 में 15.0 लाख हो गयी। जिसमे सदस्यों की मासिक आय 3500 से 5000 तक हुई।

शोध साहित्य समीक्षा :

SHGs और वित्तीय समावेशन : भट्ट और तेंदुलकर (1990) ने पाया कि SHGs वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अध्ययन के अनुसार, SHGs ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है।

नाबार्ड की भूमिका : गोपालकृष्णन (2000) के शोध में नाबार्ड की SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की सफलता को उजागर किया गया है। उन्होंने पाया कि इस पहल ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और SHGs की वित्तीय स्थिरता में सुधार किया है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण : मित्तल (2012) के अध्ययन ने दिखाया कि नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने SHGs के सदस्यों के कौशल में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इसके परिणामस्वरूप, SHGs के सदस्यों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

डिजिटल वित्तीय समावेशन : शर्मा और वर्मा (2018) ने डिजिटल वित्तीय समावेशन पर अपने अध्ययन में पाया कि नाबार्ड की पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुँच को बढ़ाया है। इससे SHGs को लाभ हुआ है और उनकी वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं में सुधार हुआ है।

शोध के उद्देश्य :

इस अध्ययन का उद्देश्य नाबार्ड की SHG क्रियान्वयन में भूमिका और उसकी विभिन्न पहल का विश्लेषण करना है। इसके अलावा, बाड़मेर जिले के एक गाँव में SHGs की सफलता की कहानी का विस्तृत विश्लेषण भी किया जाएगा।

डेटा संग्रहण :

डेटा संग्रहण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा के लिए नाबार्ड के अधिकारियों और SHG के सदस्यों के साथ साक्षात्कार और प्रश्नावली का उपयोग किया गया। द्वितीयक डेटा के लिए नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, और विद्वानों के शोध पत्रों का अध्ययन किया गया।

डेटा विश्लेषण :

डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय उपकरणों और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया। वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और डिजिटल वित्तीय समावेशन के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, बाड़मेर जिले के एक गाँव की सफलता की कहानी का भी गुणात्मक विश्लेषण किया गया।

शोध सीमाएँ :

इस शोध की सीमाएँ हैं कि यह मुख्य रूप से नाबार्ड की पहल और बाड़मेर जिले के एक गाँव तक सीमित है। अन्य क्षेत्रों और संगठनों की पहल को शामिल नहीं किया गया है।

बाड़मेर में स्वयं सहायता समूह की विकास की पहल :

राजस्थान के बाड़मेर जिले में नाबार्ड की पहल और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सहयोग से एक गाँव की महिलाएँ आत्मनिर्भर बनकर अपने समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह सफलता की कहानी न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का उदाहरण है, बल्कि सामाजिक बदलाव की भी प्रेरणादायक गाथा है।

बाड़मेर जिले का एक छोटा सा गाँव, जहाँ परंपरागत रूप से महिलाएँ घरेलू कामों में ही व्यस्त रहती थीं। इस क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों की कमी और शिक्षा का कम स्तर के कारण महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती थीं। गाँव की महिलाएँ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इच्छुक थीं, लेकिन अवसरों की कमी के कारण वे इस दिशा में कुछ नहीं कर पा रही थीं। नाबार्ड ने इस गाँव में स्वयं सहायता समूह (SHG) की स्थापना की पहल की। सबसे पहले, नाबार्ड ने गाँव की महिलाओं को संगठित किया और उन्हें SHG के लाभ और कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक किया। इसके बाद, नाबार्ड ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कौशल को विकसित करने की दिशा में कदम उठाए।

स्वयं सहायता समूह का गठन गाँव की 20 महिलाएँ ने मिलकर शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इस समूह को नाबार्ड से प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। नाबार्ड ने समूह के सदस्यों को सिलाई, कढ़ाई, और हस्तशिल्प जैसे व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया। इसके अलावा, उन्हें वित्तीय साक्षरता और बचत की महत्ता के बारे में भी जानकारी दी गई।

सफलता की यात्रा :

‘शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह’ की महिलाएँ अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके छोटे व्यवसायों को प्रारंभ करने लगीं। उन्होंने सिलाई, कढ़ाई, और हस्तशिल्प के उत्पाद बनाकर स्थानीय बाजार में बेचना शुरू किया। इन उत्पादों की गुणवत्ता और सृजनात्मकता के कारण इनकी मांग बढ़ने लगी।

‘शक्ति महिला स्वयं, सहायता समूह’ की आर्थिक प्रगति आय (रुपये में) सदस्यों की औसत मासिक आय (रुपये में) :- वर्ष 2020 में कुल आय 1,50,000 से बढ़कर 2023 में 4,50,000 हो गयी। वहीं प्रति सदस्य औसत मासिक आय 2,000 से 2023 में 5500 रुपये बढ़ी।

सामाजिक परिवर्तन : 'शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह' की सफलता न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसने गाँव में सामाजिक परिवर्तन भी किया। महिलाएँ आत्मनिर्भर होकर परिवार के आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ और उन्हें परिवार और समाज में अधिक सम्मान मिलने लगा।

शुरुआती चुनौतियाँ और समाधान : प्रारंभ में, महिलाओं को SHG की अवधारणा को समझने और इसे अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नाबार्ड ने इन चुनौतियों को दूर करने के लिए नियमित जागरूकता अभियान और सामुदायिक बैठकों का आयोजन किया। महिलाओं को समूह में शामिल होने और इसके लाभों को समझने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास : नाबार्ड ने महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन प्रशिक्षणों में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, और हस्तशिल्प जैसी कलाओं में महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, और विपणन की भी जानकारी दी गई। वित्तीय साक्षरता और बचत की आदतें नाबार्ड ने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने और बचत की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं को बैंक खाता खोलने, जमा और निकासी की प्रक्रिया, और लघु ऋण के लाभों के बारे में सिखाया गया।

उत्पादों की बाजार में पहचान : नाबार्ड ने महिलाओं के उत्पादों को स्थानीय बाजारों में पहचान दिलाने के लिए सहायता प्रदान की। समूह के उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन में सुधार करने के लिए नियमित निरीक्षण और मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही, उत्पादों को विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करने का अवसर भी मिला। सामुदायिक और पारिवारिक समर्थनरू SHG की सफलता ने गाँव में सामुदायिक और पारिवारिक समर्थन को भी बढ़ावा दिया। प्रारंभिक संदेह और प्रतिरोध के बाद, परिवारों ने महिलाओं के प्रयासों को मान्यता दी और उनका समर्थन करना शुरू किया। सामुदायिक स्तर पर भी महिलाओं की सक्रियता और उनकी भूमिका को सराहा गया।

निष्कर्ष :

बाड़मेर के इस गाँव की महिलाओं की सफलता की कहानी नाबार्ड की SHG पहल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कहानी यह दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और सहायता से महिलाएँ न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं, बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। नाबार्ड की यह पहल अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती है।

संदर्भ सूची:—

1. भट्ट, एन., और तेंडुलकर, एस. डी. (1990) स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 25(6), 345–356.
2. गोपालकृष्णन, एस. (2000) नाबार्ड के SHG–बैंक लिंकेज कार्यक्रम की सफलता जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 19(2), 167–179.
3. मित्तल, ए. (2012) नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, 8(3), 275–290.
4. नाबार्ड (2023) वार्षिक रिपोर्ट 2022–2023.
5. शर्मा, आर., और वर्मा, पी. (2018). ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन. जर्नल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिसर्च, 34(1), 1–15.
6. NRLM Annual Report (2021-2022) of Self Help Groups in India.
7. NABARD Financial Assistance Data (2010-2023).
8. NABARD Training Programs (2010-2023).



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details